

CURRENT AFFAIRS

NEWS FOR

UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

02 Jan. 2025

ABHAY SIR



ज्ञान में किए गए निवेश से सबसे
उत्तम लाभ प्राप्त होता है।

– बेंजामिन फ्रैंकलीन

Stopper l'extrémisme !

Interdiction de se
dissimuler le visage

OUI

रिक्टज़रलैंड में 1 जनवरी, 2025 से बुर्का पर बैन लागू किया गया

- ❑ इस कानून के तहत, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक होगी।
- ❑ कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 स्विस फ्रैंक (लगभग 91 हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ❑ स्विट्ज़रलैंड में बुर्का पर बैन लगाने से जुड़ी कुछ और खास बातें: साल 2021 में जनमत संग्रह के ज़रिए इस कानून को मंजूरी मिली थी. किन जगहों पर होगा
- ❑ **कानून प्रभावी :-** सार्वजनिक जगहों और निजी इमारतों में नाक, मुंह, और आंखों को बुर्के से नहीं ढका जा सकेगा. पूजा स्थलों को नए कानून में शामिल नहीं किया गया है।
- ❑ **क्यों महत्वपूर्ण है नया कानून :-** यह देश की सामाजिक संरचना और सुरक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.



□ स्विट्ज़रलैंड दुनिया का 17वां देश बन जाएगा जिसने बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले फ़्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, चीन, और श्रीलंका सहित यूरोप, एशिया, और अफ़्रीका के 16 देशों में बुर्का पर बैन लागू किया जा चुका है

□ स्विट्ज़रलैंड ऐसा कानून लागू करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया, फ़्रांस, डेनमार्क, और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के बाद। स्विट्ज़रलैंड में बुर्के और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले वस्त्रों पर प्रतिबंध की पुष्टि मार्च 2021 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से की गई थी।

□ इस जनमत संग्रह में जनता ने चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। इसे "बुर्का बैन" या "फ़ेस कवरेज बैन" के रूप में जाना जाता है।



□ प्रतिबंध की मुख्य बातें:

1. कानून का उद्देश्य:

सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, कानून का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है।

2. लागू क्षेत्र:

यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़कों, दुकानों, रेस्तरां आदि पर लागू है। धार्मिक स्थलों और अन्य कुछ परिस्थितियों में यह लागू नहीं होता।



3. राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ:

- यह प्रतिबंध स्विट्जरलैंड की दक्षिणपंथी पार्टी स्विस पीपल्स पार्टी (SVP) द्वारा समर्थित था, जो प्रवासियों और इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ कठोर नीतियों के लिए जानी जाती है। इस कदम की आलोचना करते हुए कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाला बताया।
- **प्रभाव:** यह कानून मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्का और नकाब को प्रभावित करता है। हालांकि, इसके दायरे में ऐसे अन्य चेहरे ढकने वाले मास्क या कपड़े भी आते हैं, जो किसी धार्मिक उद्देश्य से नहीं पहने जाते।





गैर-सरकारी विधेयक (Private Members' Bill)

- हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार 17वीं लोक सभा में गैर-सरकारी विधेयकों पर केवल 9.08 घंटे ही चर्चा हो सकी।

गैर-सरकारी विधेयक' के बारे में -

- गैर-सरकारी विधेयक (Private Member's Bill) संसद में पेश किया गया वह विधेयक होता है जिसे किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- गैर-सरकारी सदस्य वह सांसद होता है जो सरकार का मंत्री नहीं होता। यह विधेयक संसद में जनता के मुद्दों, सुधार, या किसी विशेष विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
- **मुख्य बिंदु:** 1. पेश करने वाले: इसे संसद के किसी भी सदस्य (जो मंत्री न हो) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

Table 22.3 Public Bill vs Private Bill

Public Bill	Private Bill
1. It is introduced in the Parliament by a minister.	1. It is introduced by any member of Parliament other than a minister.
2. It reflects of the policies of the government (ruling party).	2. It reflects the stand of opposition party on public matter.
3. It has greater chance to be approved by the Parliament.	3. It has lesser chance to be approved by the Parliament.
4. Its rejection by the House amounts to the expression of want of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation.	4. Its rejection by the House has no implication on the parliamentary confidence in the government or its resignation.
5. Its introduction in the House requires seven days' notice.	5. Its introduction in the House requires one month's notice.
6. It is drafted by the concerned department in consultation with the law department.	6. Its drafting is the responsibility of the member concerned.

- ❑ **2. उद्देश्य:** आमतौर पर यह किसी नए कानून को प्रस्तावित करने, वर्तमान कानून में संशोधन करने, या सरकार के ध्यान को किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करने के लिए होता है।

- ❑ **3. पेश करने की प्रक्रिया:** गैर-सरकारी विधेयकों को संसद के सत्र के दौरान विशेष दिनों (आमतौर पर शुक्रवार) पर पेश किया जाता है। विधेयक प्रस्तुत करने से पहले इसे लिखित रूप में नोटिस देना होता है। संसद में इसे चर्चा और मतदान के लिए रखा जाता है।

- ❑ **4. महत्व:** यह संसदीय प्रणाली में बहस और चर्चा को बढ़ावा देता है। यह विधायकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और सरकार की जवाबदेही तय करने का मंच प्रदान करता है।



❑ **5. सफलता दर:** गैर-सरकारी विधेयकों की सफलता दर बहुत कम होती है क्योंकि आमतौर पर सरकार इनका समर्थन नहीं करती। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक केवल कुछ ही गैर-सरकारी विधेयक कानून बने हैं।

❑ **ऐतिहासिक उदाहरण:** शादी के कानून में सुधार विधेयक (1956), जिसे हरिविष्णु कामथ ने प्रस्तुत किया था, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। गैर-सरकारी विधेयक लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों के बीच संवाद और विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

PRIVATE MEMBER'S BILLS PASSED BY PARLIAMENT			
Title	MP's Name	House	Date of Assent
1 The Muslim Wakfs Bill, 1952	Syed Mohammed Ahmed Kasmi	Lok Sabha	21.05.1954
2 The Indian Registration (Amendment) Bill, 1955	S C Samanta	Lok Sabha	06.04.1956
3 The Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1956	Feroze Gandhi	Lok Sabha	26.05.1956
4 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1953	Raghunath Singh	Lok Sabha	01.09.1956
5 The Women's and Children's Institutions (Licensing) Bill, 1954	Kamledu Mati Shah	Lok Sabha	30.12.1956
6 The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1957	Subhadra Joshi	Lok Sabha	26.12.1960
7 The Salary and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1964	Raghunath Singh	Lok Sabha	29.09.1964
8 The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1963	Diwan Chand Sharma	Lok Sabha	20.12.1964
9 The Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Bill, 1968	Anand Narian Mullah	Lok Sabha	09.08.1970
10 The Ancient and Historical Monuments and Archeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Bill, 1954	Dr Raghubir Singh	Rajya Sabha	15.12.1956
11 The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1956	Dr Seeta Parmanand	Rajya Sabha	20.12.1956
12 The Orphanages and Other Charitable Homes (Supervision and Control) Bill, 1960	Kailash Bihari Lall	Rajya Sabha	09.04.1960
13 The Marine Insurance Bill, 1959	MP Bhargava	Rajya Sabha	18.04.1963
14 The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1963	Diwan Chaman Lall	Rajya Sabha	07.09.1969



स्वेज नहर

- मित्र के द्वारा स्वेज नहर के नए चैनल के विस्तार का परीक्षण पूरा कर लिया गया है।
- **स्वेज नहर (Suez Canal)** एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह नहर मित्र में स्थित है और एशिया व यूरोप के बीच समुद्री यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त मार्ग है।
- स्वेज नहर का निर्माण समुद्री मार्ग को छोटा और सुगम बनाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे (केप ऑफ गुड होप) से होकर न गुजरना पड़े।
- **अवस्थिति:** यह मित्र में स्वेज स्थलसंधि को पार करते हुए मानव निर्मित जलमार्ग है।



□ स्वेज नहर का संक्षिप्त परिचय:

□ 1. **निर्माण और उद्घाटन:** इस नहर का निर्माण 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में शुरू हुआ। 10 वर्षों के बाद, 1869 में इसे आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया।

□ 2. **स्थान:** स्वेज नहर मिस्र में है और यह उत्तर में पोर्ट सईद (Port Said) और दक्षिण में स्वेज शहर (Suez City) को जोड़ती है। चैनल का दो-तरफ़ा खंड अब 72 किमी से 82 कि.मी. तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई लगभग 193 किलोमीटर है।

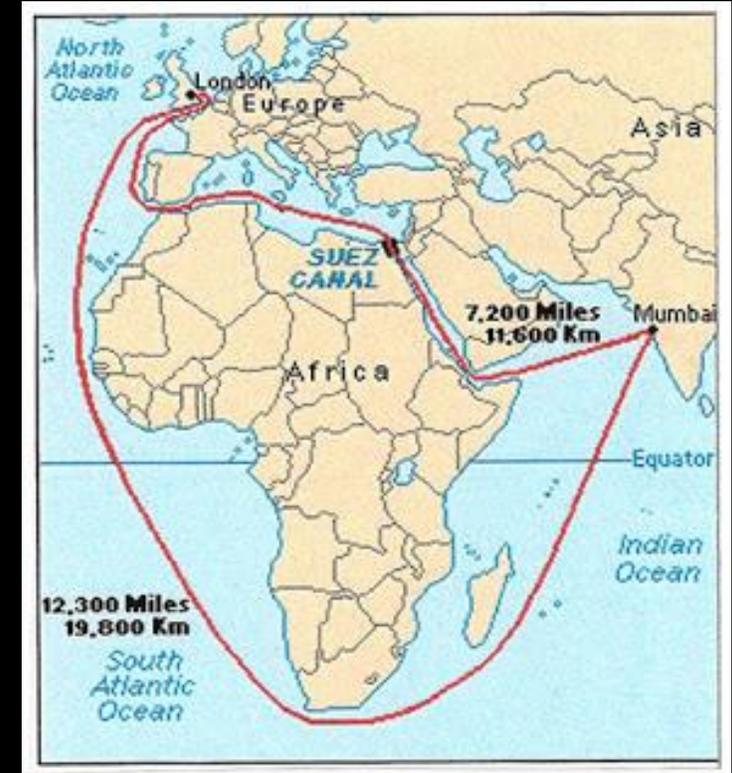
□ 3. **महत्व:** यह नहर यूरोप और एशिया के बीच सबसे तेज़ समुद्री मार्ग प्रदान करती है। यह वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के लगभग 12% समुद्री व्यापार का संचालन इस मार्ग से होता है।



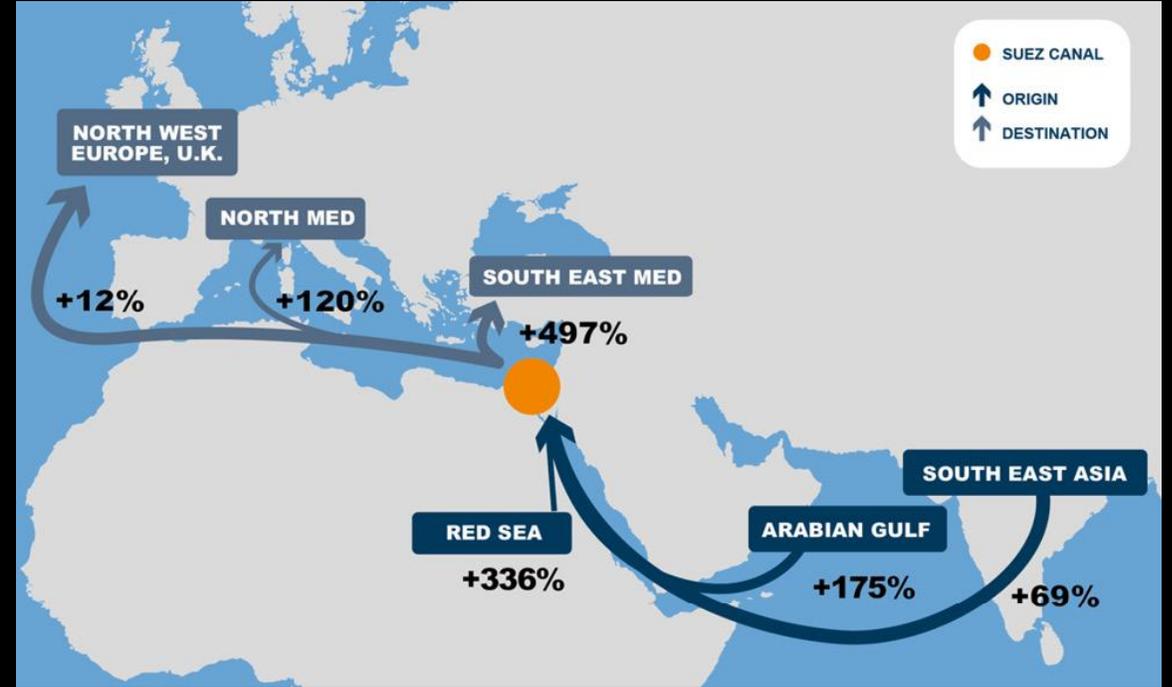
❑ **4. विशेषताएँ:**स्वेज नहर को लॉक-लेस नहर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जहाजों को उठाने-गिराने के लिए किसी लॉक सिस्टम की जरूरत नहीं होती। यह समुद्र के जल स्तर पर है, जिससे जहाज सीधे गुजर सकते हैं।

❑ **5. प्रबंधन:**वर्तमान में स्वेज नहर का प्रबंधन और संचालन स्वेज नहर प्राधिकरण (Suez Canal Authority) द्वारा किया जाता है।

❑ **6. ऐतिहासिक महत्व:**1956 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर ने नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे स्वेज संकट (Suez Crisis) हुआ। इस घटना ने इसे वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण विषय बना दिया।



□ **7. आर्थिक महत्व:**स्वेज नहर से होकर जाने वाले जहाजों से मिस्र सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है। यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस के कई जहाज इस नहर से गुजरते हैं। स्वेज नहर न केवल व्यापारिक दृष्टि से, बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थल है।



M

S

P

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

□ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है।

□ उद्देश्य :- किसानों को उनकी उपज के लिए एक निश्चित मूल्य की गारंटी देना, ताकि बाजार में कीमतें गिरने पर भी उन्हें नुकसान न हो।

□ यह प्रणाली किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।

□ MSP का निर्धारण कैसे :- MSP के निर्धारण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं:

□ कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACAP) की सिफारिशें: CACP विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत, बाजार की मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझान, और किसानों की आय को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फसल के लिए MSP की सिफारिश करता है।

MSP

source: NITI Aayog's report on Evaluation of efficacy of MSP on Farmers , 2016
prepared by: suresh.wordpress.com

<p>Andhra Pradesh</p> <p>Farmers were aware of MSP rate and most of them sold their crops at MSP. There was discontentment among the farmers regarding MSP not covering costs; however, they were in support of continuance of MSP to avoid exploitative practices</p>	<p>Bihar</p> <p>Farmers knew about MSP but the awareness about the time of their announcement was very low. The reason for not selling at MSP was that the purchase centers were located at distance which required high transportation costs.</p>
<p>Gujarat</p> <p>33 percent of farmers were aware of MSP and the time of their declaration. MSP determines the market prices so farmers indirectly benefit from it. It also provides psychological support as it insulates farmers from the possibility of low prices.</p>	<p>Karnataka</p> <p>Majority of the households, government representatives and knowledgeable persons were in favour of continuance of MSP. MSP prevented the wholesale prices from falling, and it also ensures guaranteed income to the farmers by acting as a floor price</p>
<p>Madhya Pradesh</p> <p>The MSP has not been able to show much influence as many of the farmers were not even aware of MSP</p>	<p>Maharashtra</p> <p>About 56 per cent of the selected farm households opined that the MSP should continue as a guaranteed price is ensured to the farmers.</p>
<p>Rajasthan</p> <p>56 per cent of the households were aware of MSP. Out of them 22 per cent knew about MSP before the sowing season and 38 per cent after the sowing season.</p>	<p>Tamil Nadu</p> <p>The MSP for paddy was remunerative since the rate of increase in MSP (32%) during the reference period was greater than the rate of increase in the cost of cultivation.</p>
<p>Uttar Pradesh</p> <p>All the farmers were aware of MSP but none of them knew it before the sowing season. All knowledgeable persons were in favour of continuation of MSP and people on the whole have benefitted from it</p>	<p>Uttarakhand</p> <p>MSP should continue as it provides assured market to their produce, it determined the floor price and also ensured a guaranteed returns for the produces</p>

□ **सरकारी विचार-विमर्श:** CACP की सिफारिशों पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों के आधार पर MSP निर्धारित करती है।

□ **अंतिम निर्णय:** केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) MSP के स्तर और CACP द्वारा दी गई अन्य सिफारिशों पर आखिरी फैसला लेती है।

□ MSP की गणना में शामिल लागतें CACP उत्पादन लागत का आकलन तीन श्रेणियों में करता है:

□ **A2:** इसमें किसानों द्वारा सीधे किए गए खर्च शामिल होते हैं, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और श्रम का खर्च।

□ **A2+FL:** इसमें A2 लागत के साथ-साथ उन पारिवारिक सदस्यों की मेहनत का भी मूल्य जो खेती में बिना मजदूरी लिए काम करते हैं।

Better support



The Cabinet increased the minimum support prices for rabi crops

Crop	MSP for rabi 2025-26*	MSP for rabi 2024-25*	Increase in MSP
Wheat	₹2,425	₹2,275	₹150
Barley	₹1,980	₹1,850	₹130
Gram	₹5,650	₹5,440	₹210
Lentil (masoor)	₹6,700	₹6,425	₹275
Rapeseed & mustard	₹5,950	₹5,650	₹300
Safflower	₹5,940	₹5,800	₹140

(*per quintal)

□C2: यह सबसे विस्तृत लागत है, जिसमें A2+FL के अलावा, किसान की अपनी जमीन का किराया और उसके द्वारा उपयोग की गई पूंजी पर ब्याज भी जोड़ा जाता है।

□न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत कवर की गई फसलें भारत सरकार वर्तमान में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करती है, जो निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:

- | | | |
|----------|--------------|----------------|
| 1. अनाज | 10.चना | 19. तिल |
| 2. धान | 11.अरहर/तूर | 20. सूरजमुखी |
| 3. गेहूं | 12.मूंग | 21. सफ़फ़लौंवर |
| 4. मक्का | 13. उड़द | 22. नाइजरसीड |
| 5. ज्वार | 14.मसूर | |
| 6. बाजरा | 15.तिलहन | |
| 7. रागी | 16.मूंगफली | |
| 8. जौ | 17.राई/सरसों | |
| 9. दालें | 18.सोयाबीन | |



□ वाणिज्यिक फसलें

1. कपास
2. जूट
3. नारियल

इसके अतिरिक्त, गन्ना के लिए 'उचित और लाभकारी मूल्य' निर्धारित किया जाता है।

□ कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में की गई थी और 1985 में इसका वर्तमान नाम दिया गया।

□ CACP की भूमिका और कार्य:

□ MSP की सिफारिश: CACP विभिन्न फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और वे नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हों।



□ **लागत विश्लेषण:** आयोग उत्पादन लागत, बाजार मूल्य, मांग और आपूर्ति, और किसानों की आय जैसे कारकों का विश्लेषण करता है ताकि उचित MSP निर्धारित किया जा सके।

□ **नीतिगत सलाह:** CACP सरकार को कृषि मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतिगत सलाह भी प्रदान करता है।

□ **मुख्य बिंदु:**

□ **1. उद्देश्य:** किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाना। किसानों को उनकी लागत के मुकाबले न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित करना। फसल की बर्बादी और संकट की स्थिति में सहायता प्रदान करना।

Advantages

The minimum support prices are a guarantee price for their produce from the Government.

MSP is announced before the sowing season so that the farmers can make an informed decision.

The major objectives are to support the farmers from distress sales and to procure food grains for public distribution.

It ensures adequate food grain production in the country.

In case the market price for the commodity falls below the announced minimum price due to bumper production and glut in the market, government agencies purchase the entire quantity offered by the farmers at the announced minimum price.

MSP thus increases the farmers' income which they can invest in new technology.

It also helps in achieving the Government's goal of doubling farmers income by the year 2022.

Disadvantages

MSP is devoid of any legal backing. Access to it, isn't an entitlement for farmers. They cannot demand it as a matter of right. The government can procure at the MSPs if it wants to. The only crop where MSP payment has some statutory element is sugarcane.

MSP has not increased in proportion to the cost of production.

CACP is just "an attached office of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare". It can recommend MSPs, but the decision on fixing and enforcement rests finally with the government.

Though government announces MSP for 23 crops, it procures only 1/3rd of those.

There is lack of awareness amongst farmers and there is regional variation in implementation.

It kills competition and puts pressure on government finances.

The system has been often criticised at WTO platform.

□2. **फसलों की सूची:**सरकार विभिन्न फसलों के लिए MSP घोषित करती है, जैसे धान, गेहूं, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना आदि।

□वर्तमान में, लगभग 23 फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है।3. **लाभ:**किसानों को बाजार के दाम गिरने की स्थिति में सुरक्षा मिलती है।खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने में मदद मिलती है।खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन।

□4. **चुनौतियाँ:**सभी किसानों को MSP का लाभ नहीं मिल पाता, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को।सरकारी खरीद केंद्रों की कमी।

□MSP और बाजार मूल्य के बीच अंतर को लेकर विवाद।

□MSP और बाजार मूल्य के बीच अंतर को लेकर विवाद

MSP का महत्व:

□MSP भारतीय कृषि क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने और किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, इसे और प्रभावी बनाने के लिए नीतिगत सुधार और बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।



पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक कर पाकिस्तानी तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया।

□ ये हमले पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के पकटिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में किए गए। इस एयरस्ट्राइक में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं।

□ न्यूज एजेंसी AP ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि हमले में पाकिस्तानी तालिबान यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया गया है। अधिकारियों ने कई आतंकियों के मरने का दावा किया।

□ हालांकि, ये साफ नहीं है कि पाकिस्तानी विमान अफगानिस्तान में कितने भीतर गए और हमले कैसे किए गए। मार्च के बाद दूसरी बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की है।



□ अफगानिस्तान बोला- जवाबी कार्रवाई करेंगे

□ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की निंदा की है। काबुल ने आरोप लगाया कि बमबारी में महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है।

□ अफगानिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर नाराजगी जताई।

□ मंत्रालय ने लिखा कि इस तरह के एकतरफा कदम किसी समस्या का समाधान नहीं हैं। अफगानिस्तान ने एयरस्ट्राइक का जवाब देने की बात कही।



□ मंत्रालय ने लिखा, 'अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा अधिकार है, हम इस कायरतापूर्ण हमले का जवाब जरूर देंगे।'

□ 2022 से TTP ने पाकिस्तान पर हमले तेज किए पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान के जमीन का इस्तेमाल करके उस पर आतंकी हमले करता है। हालांकि पाकिस्तान के इन आरोपों को अफगानिस्तान ने खारिज करता रहा है।

□ अफगानिस्तान में 2021 के तालिबान की वापसी के साथ ही पाकिस्तानी तालिबान (TTP) मजबूत हुआ है। TTP ने नवंबर 2022 में पाकिस्तान के साथ सीजफायर को एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया था।



□ इसके बाद उसने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ महीनों में TTP ने पाकिस्तान के कई सैनिकों और पुलिसकर्मियों की हत्या की है।

□ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शनिवार तड़के आतंकवादियों ने सेना की पोस्ट पर हमला किया। इसमें 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। घटना अफगानिस्तान बॉर्डर से 40 किमी दूर माकिन में हुई है।

□ न्यूज एजेंसी एएफपी ने सेना के अधिकारी के हवाले से बताया कि 30 से ज्यादा आतंकवादियों ने सेना के पोस्ट पर करीब 2 घंटे तक हमला किया। इस दौरान आतंकवादियों ने चौकी पर मौजूद वायरलेस उपकरण, दस्तावेज समेत कई चीजों में आग लगा दी।



□ इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए हमले के बाद से इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। घटनास्थल के पास आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस घटना की जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों ने ली है।

□ कई अहम हथियार लूटकर आतंकी फरार आतंकवादियों ने सैन्य चौकी पर किए हमले को अपने सीनियर कमांडरों की शहादत का बदला बताया।

□ रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान आतंकवादियों ने मशीन गन, नाइट विजन तकनीक सहित कई जरूरी सैन्य उपकरण लूट लिए। हाल ही में 18 दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने तीन अलग-अलग कार्रवाई की थी जिसमें 11 आतंकवादियों को मारने का दावा किया था।



□ 25 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान इलाके में TTP आतंकियों ने हमला किया था। जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए थे। यह इलाका अफगानिस्तान बॉर्डर से करीब 70 किमी दूर है।

□ क्या है TTP ?

□ साल 2007 में कई सारे आतंकी गुट मिलकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बनाया। TTP को पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। पाकिस्तानी सरकार ने अगस्त 2008 में TTP को बैन कर दिया था। अक्टूबर 2001 में अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान की सत्ता से तालिबान को बेदखल किया तो कई आतंकी भागकर पाकिस्तान में बस गए थे।



□ इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान पाकिस्तान की सेना इस्लामाबाद की लाल मरिजद को एक कट्टरपंथी प्रचारक आतंकी के कब्जे से मुक्त कराया। इस घटना के बाद स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी की खिलाफत होने लगी।

□ इससे कबाइली इलाकों में कई विद्रोही गुट बनने लगे। इसके बाद दिसंबर 2007 को बेतुल्लाह मेहसूद की अगुआई में 13 गुटों ने एक तहरीक यानी अभियान में शामिल होने का फैसला किया। संगठन का नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान रखा गया।



THANK YOU



@resultmitra / 8650457000



@resultmitra



@resultmitra



Result

